

संपादकीय

आस्था पर आघात

अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए दान और कीमती सामान की हेराफेरी की घटनाओं ने देश-विदेश की समस्तों को विचलित किया है। कभी आमजन में कहा जाता था कि 'भगवान से डर', लेकिन पैसे की हवस देखिए कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े चंद लोगों ने भगवान के घर में चोरी करने में कोई डर महसूस नहीं किया। ये प्रबंधन व व्यवस्था की पारदर्शिता की खोटा तो है ही, मानवीय मूल्यों के पतन की पराकाष्ठा भी है कि मंदिर में चढ़ावे की देखरेख को तेनात लोग ही चोरी-चकारी में लिप्त हो जाएं। इस मामले में विपक्ष के तीखे हमले और जनक्रोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए आनन-फानन में एसआईटी गठित की, रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, प्राथमिकी दर्ज की और वीरवार को प्रबंधन से जुड़े आठ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई गई। लेकिन अपने आराध्य राम के चढ़ावे की चोरी से आहत भक्तों के जख्मों पर शायद तभी मरहम लगो, जब दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। निश्चित ही यह चोरी का प्रकरण भाजपा व संघ को परेशान करने वाला है। उस राजनीतिक दल के लिये, जिसके कभी दो सांसद हुआ करते थे और राम मंदिर की मुहिम से हासिल जनसमर्थन से केंद्र व तमाम राज्यों में उसकी सरकारें बनी हैं। खासकर, भाजपा के लिए यह मुद्दा परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि राम जन्म भूमि वाले प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस मुद्दे को लेकर भाजपा राज्य की सत्ता में आती रही है, उस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर होगा। निस्संदेह, इस प्रकरण से राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट तो पहुंची है। सवाल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी पर भी उठेगी उसने समय रहते इस चोरी को क्यों नहीं पकड़ा। बेहतर होता कि दोषियों के खिलाफ ट्रस्ट की तरफ से स्वतः प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाती। सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ट्रस्ट चंदे की रकम का हिसाब-किताब विश्वसनीय तरीके से नहीं रख पाया।

निश्चय ही इस प्रकरण से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की साख भी दांव पर लगी है। वह उन भक्तों की भावनाओं की रक्षा नहीं कर पाया, जिन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर अब तक दिल खोलकर दान दिया। जब चंदा प्रबंधन से जुड़े लोगों के घर से लाखों की नकदी बरामद हुई और चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के आरोप सामने आए तो भक्तों की आस्था पर आंच आना स्वाभाविक ही है। आरोप सिर्फ नकदी के हेरफेर के ही नहीं लगे बल्कि कीमती गहनों को खुरदबुर करने के भी लगे। वहीं प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दान में मिली चांदी की छड़ों के गहनों की आस्था को भी आरोप है। बहरहाल, २०२७ के यूपी विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले सामने आए इस विवाद ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष जहां दोषियों पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा इन आरोपों को अयोध्या को बदनाम करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बता रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि जिन भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए पांच सौ साल तक इंतजार किया, उन्हें एसआईटी जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। उनकी दलील है कि इस घटनाक्रम मामले को तब तक जाने के लिये एक पारदर्शी और सम्य-सीमा के भीतर होने वाली जांच बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल चंदे के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और स्वतंत्र ऑडिट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के दान और धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह प्रकरण देश के बड़े धार्मिक संस्थानों में चंदे के प्रबंधन में पारदर्शिता व सतर्कता की मांग करता है। चंदे का नियमित ऑडिट किया जाना, तकनीक आधारित प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी वाले आधुनिक सिस्टम की जरूरत को दर्शाता है। निस्संदेह, राम मंदिर भारत विदेशों में बसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आकांक्षा का प्रतीक है। श्रद्धालुओं का भरोसा बनाये रखने के लिये हर आक्षेप की पारदर्शिता से जांच जरूरी है।

सड़क बहने से 10-12 गांवों का संपर्क टूटा

अब आवागमन की समस्या हुई गंभीर, ३० किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करने परिसर के ग्रामीण हुए मजबूर

संवाददाता। कारंजा घाडगे

कारंजा-सावरडोह मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का कार्य समय पर पूरा नहीं होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल निर्माण के दौरान आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्जन मार्ग बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश में बह गया, जिससे सावरडोह सहित आसपास के १० से १२ गांवों का संपर्क कारंजा शहर से पूरी तरह कट गया है।

ग्रामीणों के अनुसार पुल निर्माण कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है। बरसात शुरू होने से पहले पुल का निर्माण पूरा नहीं किया गया और न ही डायवर्जन मार्ग को सुरक्षित एवं मजबूत बनाया गया। बारिश का पानी बढ़ते ही अस्थायी मार्ग बह गया, जिसके कारण इस मार्ग पर सभी



प्रकार की आवाजाही बंद हो गई है। मार्ग बंद होने के बाद ग्रामीणों को कारंजा पहुंचने के लिए लगभग ३० किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे रोजमर्रा के कामकाज, विद्यार्थियों, मरीजों और

नौकरीपेशा लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर दुग्ध उत्पादक किसानों पर पड़ा है। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रतिदिन दूध संग्रहण केंद्र तक समय पर

प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें काम

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए। साथ ही, जब तक पुल तैयार नहीं हो जाता, तब तक आवागमन के लिए सुरक्षित और मजबूत वैकल्पिक मार्ग तत्काल उपलब्ध कराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। इस ओर अनदेखी करने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी ग्रामीणों ने प्रशासन को दी है।

दूध पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। लंबा रास्ता तय करने के कारण समय और परिवहन लागत दोनों बढ़ गई हैं, वहीं दूध खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। मानसून के साथ कृषि कार्य भी तेज हो गए हैं, बुआई के लिए आवश्यक बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री शहर से गांवों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है।

अतिरिक्त दूरी तय करने के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और

खेती की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की धीमी गति और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन और संबंधित ठेकेदार ने बरसात को देखते हुए डायवर्जन मार्ग की पर्याप्त सुरक्षा और मजबूती का ध्यान नहीं रखा। यदि समय रहते आवश्यक व्यवस्था की जाती तो आज क्षेत्र के हजारों लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मांगी रिपोर्ट

वर्धा : पहली कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु पूरी होने के बावजूद एक छात्र को स्कूल में प्रवेश न दिए जाने का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), नई दिल्ली ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वर्धा के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वर्धा के नागसेन नगर रोड निवासी हर्षवर्धन गोडघाटे के बेटे राजरत्न को महिला आश्रम संचालित बुनियादी प्राथमिक मराठी विद्यालय में पहली कक्षा में

प्रवेश नहीं दिया गया। अभिभावक का आरोप है कि उनके बेटे ने प्रवेश के लिए आवश्यक आयु सीमा और केजी-२ की शिक्षा पूरी कर ली थी, इसके बावजूद विद्यालय ने उसे पहली कक्षा में दाखिला देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में हर्षवर्धन गोडघाटे ने पहले जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का दरवाजा खटखटाया।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का है मामला

आयोग के अनुसार, ई-बाल निदान पोर्टल पर प्राप्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि राजरत्न गोडघाटे को जानबूझकर शिक्षा से वंचित रखा गया है, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) २००९ की धारा ३ का संभावित उल्लंघन हो सकता है। आयोग के निदेशक वी. रामानाथा रेड्डी ने १७ जून को वर्धा के जिलाधिकारी को पत्र जारी कर मामले की विस्तृत जांच करने तथा नियमानुसार कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह मामला सीधे तौर पर एक बच्चे के शिक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। अब आयोग के हस्तक्षेप के बाद सभी को नजर जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर लगी है।

एक गिरफ्तार, साथी फरार, 1.1.3 किलो चंदन जब्त

नागपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के नागपुर स्टेशन के दौरे के वक्त शासकीय रेलवे पुलिस का बम निरोधक एवं श्वान दस्ता (बीडीडीएस) जब जांच में जुटा था, तभी उनके हाथ एक चंदन तस्कर लग गया। शुक्रवार सुबह हुई इस कार्रवाई में रेलवे पुलिस ने चंदन तस्कर को हिरासत में लेकर उसके पास से टुकड़ों के रूप में ११ किलो ३०० ग्राम चंदन की लकड़ी जब्त की।

संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को राजधानी एक्सप्रेस से बैंगलुरु जा रहे थे। ऐसे में एहतियात के तौर पर रेलवे पुलिस ने स्टेशन और परिसर में कड़ा बंदोबस्त लगाया था। बीडीडीएस टीम शुक्रवार सुबह करीब ७:३० बजे प्लेटफॉर्म १ पर गहन जांच में जुटी थी। तभी उसे एक शख्स संदिग्ध हालत में बैग के साथ दिखाई दिया। बीडीडीएस टीम ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इसमें वह ढुलमुल जवाब देने लगा।

इससे संदेह बढ़ने पर रेलवे

आरोपी जा रहा था हरिद्वार

इस घटनाक्रम के बाद चंदन की तस्करी करने के आरोप में दिनेश माणिकराव राउत (३५) को हिरासत में लिया गया। वह काटोल तहसील के गोन्ही गांव निवासी है। उसने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि वह हरिद्वार जा रहा था। इस बीच, जब उससे पूछताछ चल रही थी, तभी उसका दूसरा संदिग्ध साथी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से खिसक गया। पुलिस और वन विभाग की टीम अब उसकी तलाश कर रही है। जीआरपी के पुलिस अधीक्षक मोश शिंदे के मार्गदर्शन में बीडीडीएस के प्रभारी पीएसआई योगेश कातुरे और उनके सहयोगियों ने ये कार्रवाई की।



पुलिस ने बीडीडीएस के 'योद्धा' नामक खोजी श्वान से उसके बैग की जांच कराई। इसमें योद्धा ने संकेत दिए कि बैग में बम जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन कुछ अलग जरूर है। ऐसे में बीडीडीएस के पीएसआई योगेश कातुरे ने

जीआरपी के थाना प्रभारी गौरव गावंडे को तत्काल सूचना दी। वे अपने दस्ते के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इसके बाद बैग को खोलकर जांचा गया। इस दौरान बैग में ११ किलो ३०० ग्राम चंदन की लकड़ी के टुकड़े मिले। ऐसे में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वनपाल जितेंद्र बघेले और उनकी टीम द्वारा यह चंदन की लकड़ी होने की पुष्टि करने पर इसे जब्त कर लिया गया। लोकमत समाचार से बातचीत में अधिकारियों ने प्राथमिक अनुमान बताया कि जब्त की गई चंदन की लकड़ी की कीमत १ से १.२५ लाख रुपए के बीच है।

एलसीबी की कार्रवाई में १०४ ग्राम एमडी जब्त की गई, ६.२३ लाख का माल बरामद

शहर के मध्यभाग में पानठेले पर बेच रहा था एमडी शहर में युवकों के जीवन से खेला जा रहा है जानलेवा खेल



और भी गिरफ्तारी संभव, खुलासे भी होंगे

रामनगर पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे ने बताया कि क्राइम ब्रांच इस ड्रग की बिक्री और वित्तीय लेनदेन की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही है। इस मामले में जल्द ही और खुलासे होंगे और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है।

चंद्रपुर : शहर के मध्यम भाग में पानठेले पर एमडी बेचे जाने की जानकारी मिलने पर स्थानीय अपराध शाखा ने चंद्रपुर शहर के जटपुरा गेट इलाके में स्थित इटनकर पान की दुकान पर छापा मारा। इस कार्रवाई में १०४.२१० ग्राम एमडी पाउडर, मोबाइल और कुल ६.२३ लाख रुपए माल जब्त किया गया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें २५ वर्षीय ओम संतोष उर्फ बापू इटनकर और इरफान उर्फ भूरिया पठान शामिल हैं। दोनों पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच को गोपनीय

सूचना मिली थी कि शहर के मशहूर इटनकर पान स्टॉल पर एमडी पाउडर बेचा जा रहा है। सूचना के आधर पर, एलसीबी के पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे के नेतृत्व में एक टीम ने इटनकर पान की दुकान पर छापा मारा। ओम इटनकर को हिरासत में लिया गया और घर की तलाशी ली गई, जिसमें १०४.२१० ग्राम एमडी पाउडर, २ मोबाइल फोन जब्त किए गए।

आरोपी ओम इटनकर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने एमडी पाउडर बागडि खिड़की इलाके के निवासी इरफान उर्फ भूरिया पठान से खरीदा था। पुलिस ने इरफान उर्फ भूरिया पठान को भी

गिरफ्तार कर लिया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े और अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक विनोद भुरले, उपनिरीक्षक सुनील गौरकर, उपनिरीक्षक संतोष निंबोरकर, उपअधीक्षक डोके, पुलिस टीम में सतीश अवताडे, रजनीकांत पट्टावार, दीपक डोंगरे, इमरान स्वान, सुनील अत्राम, हीरालाल गुप्ता, किशोर वाकारे, शशांक बादामवार, प्रतीक हेमके, छाया, अपर्णा, राजेश किन्नाके और विनोद चव्हाण ने की।

दूरदर्शिता रखकर विकास प्रस्ताव तैयार करें : कलेक्टर

देश के टॉप-१० आकांक्षित जिलों में शामिल गढ़चिरोली, समीक्षा बैठक में हुई चर्चा

गढ़चिरोली : जिलाधिकारी अविशांत पंडा ने कहा कि केंद्र सरकार के 'आकांक्षित जिला' अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गढ़चिरोली जिले ने देश के ११२ आकांक्षित जिलों की सूची में पहले १० में जगह बनाई है। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन फंड वितरण में जिले ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए सभी एजेंसियों को केवल अस्थायी योजना न बनाकर, आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी और नवाचारी विकास प्रस्ताव तैयार करने की निर्देश दिए। नीति आयोग के सलाहकार दधिच इंद्रोदिया जिले में तीन दिवसीय दौर पर आए हैं। जिलाधिकारी



कार्यालय में २५ जून को आयोजित समग्र समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी बोल रहे थे। इस बैठक में गढ़चिरोली जिला और आकांक्षित विकासखंडों (अहरी, सिरोंचा, भामरागढ़) क्षेत्र के विविध विकास मुद्दों पर

यहां चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिलाधिकारी एम. अरुण, उपवन संरक्षक श्रीमती आर्या, जिला नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे, जिला स्वास्थ्य

नीति आयोग का दौरा और क्षेत्रवार समीक्षा

नीति आयोग के सलाहकार दधिच इंद्रोदिया ने पिछले तीन दिनों में जिले के जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों का सीधे दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले अधिकारी, कर्मियों की प्रतिबद्धता की खास तारीफ की।

अधिकारी डॉ. प्रतीप शिंदे, जिला शाल्य चिकित्सक डॉ. माधुरी किलनाके और जिला अधीक्षक तथा कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर उपस्थित रही और उन्होंने अपने-अपने विभाग की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बारिश का बैकलॉग बढ़ा, उमसभरी गर्मी कर रही बेहाल, पारा ३६.४ डिग्री पर बैकलॉग भरने के आसार नहीं!



नागपुर : नागपुर में लगभग सप्ताहभर विलंब से मानसूनी मेघों के पहुंचने की घोषणा मौसम विभाग की तरफ से कर दी गई। मानसूनी मेघ पूरी खामोशी से शहर को पार कर पड़ोसी राज्य पहुंच गए। पर शहरवासी अब भी जोरदार मानसूनी बारिश के इंतजार में हैं। कब जोरदार बारिश होगी, इसे लेकर कोई स्पष्ट अनुमान लगा पा रहा। मौसम के जानकारों ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जून के बचे हुए दिनों में बारिश का बैकलॉग दूर होने के आसार नहीं हैं। नागपुर में जून के बीते २५ दिनों में सामान्य से ३३ फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई है। जबकि विदर्भ की बात करें तो यहां सामान्य से ५४ फीसदी कम बारिश हुई है। विदर्भ स्तर पर अब तक ६०.३ मिमी वर्षा हुई, जबकि सामान्यतः संबंधित अर्धदिन में १३१.२ मिमी वर्षा होती है। नागपुर

में शुक्रवार को दिन का तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक ३६.४ डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा जबकि दिनभर आसमान में बादलों का डेरा रहा। लेकिन खुलकर बादल नहीं बरसे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की खबर है। दिन में बादलों की वजह से आर्द्रता ६८ फीसदी पर जा पहुंची। आगामी दो से तीन दिनों तक तेज बारिश होने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश से पूर्व मध्यप्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना तक एक द्रोणिका तैयार हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से म्यांमार के बीच अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और कम दबाव का क्षेत्र तैयार नहीं होने की वजह से ही विदर्भ के जिलों में बारिश का जोर नहीं दिखाई दे रहा।

केंद्रीय स्कूल संवारेगा आदिवासी छात्राओं का भविष्य

गढ़चिरोली में केंद्रीय विद्यालय मंजूर, जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने ली बैठक

संवाददाता। गढ़चिरोली

सरकार ने गढ़चिरोली जिले के दूरदराज क्षेत्र के आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन को जिले में स्वीकृत किए गए केंद्रीय विद्यालय का शुरु करने का निर्देश दिया है। इस शैक्षणिक सत्र से इस स्कूल को शुरु करने के संदर्भ में जिला प्रशासन ने गतिविधियां शुरु कर दी हैं।

जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा की उपस्थिति में सोमवार, २२ जून को उनके कार्यालय में अधिकारियों की इस विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ठक



में आदिवासी विकास विभाग की ओर से कार्यान्वित एकलव्य मॉडल निवासी स्कूल और सरकारी आश्रम स्कूलों की विविध लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई। जिले के दूरदराज अंचल के विद्यार्थियों में फिरे हुए गुणों को अजागर करने के लिए उनके

खेल, विज्ञान के साथ-साथ कला और संस्कृति के क्षेत्रों में उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उम्र अनुसार मैप करके विस्तृत डेटाबेस तैयार करने के सख्त निर्देश भी बैठक में अधिकारियों को दिए गए। बैठक में आदिवासी विकास विभाग के

तीन प्रमुख क्षेत्रों में छात्रों का वर्गीकरण

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए साइंस इन्वेषन, स्पोर्ट्स और आर्ट एवं कल्चर इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में छात्रों का वर्गीकरण करके उनकी जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए गए। कक्षा छठी से आठवीं, आठवीं से दसवीं और ग्यारहवीं से बारहवीं के आयु समूह के अनुसार छात्रों का मैनिंग करके जिला स्तर पर अलग डेटाबेस बनेगा और इसके तहत प्रतिभाशाली छात्रों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल और विज्ञान प्रतियोगिता तथा विभिन्न राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

परियोजना अधिकारी अरुण एम., जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अस्मिता मोरे, शिक्षण अधिकारी वासुदेव धुसे और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

एकलव्य स्कूल का चामोर्शी में स्थानांतरण

चामोर्शी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और गढ़चिरोली में मौजूदा स्कूल को उसके मूल स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद, उपलब्ध स्थान पर नए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालयों को शुरु करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए।

तालाब और नदी सफाई में नई तकनीक की हुई एंट्री

पुणे में 'फ्लोटिंग स्पाइडर मशीन' का सफल ट्रायल, महापौर मंजुषा नागपुरे ने पूरे प्रयोग का किया निरीक्षण



पारंपरिक तौर-तरीके छोड़ आधुनिक तकनीक का सहारा

इन गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से वैज्ञानिक ढंग से निपटने के लिए पुणे मनाया अब पारंपरिक तौर-तरीकों को छोड़कर इस आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है. जांभूलावाडी तालाब में आयोजित इस विशेष प्रयोग के दौरान फ्लोटिंग स्पाइडर मशीन ने पानी की सतह पर बेहद सुगमता से तैरते हुए जलकुंभी और अन्य जलीय वनस्पतियों को उखाड़ने तथा उन्हें बाहर निकालने की अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया. इस मशीन की बनावट ऐसी है कि यह जलाशयों के बेहद गहरे और संकरे हिस्सों तक भी आसानी से पहुंचकर वहां जमा कचरे और खरपतवार की सफाई कर सकती है.

सफाई का काम बेहद आसान और तीव्र होगा, बल्कि जल प्रदूषण नियंत्रण और जलीय जैव विविधता के संरक्षण में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी.

जलकुंभी के फैलाव से पानी का प्रवाह होता है बाधित : जलकुंभी के बेकाबू फैलाव के कारण तालाबों और नदियों में पानी का स्वाभाविक प्रवाह पूरी

प्रभावी तरीके से हो सकेगी सफाई

इस महत्वपूर्ण तकनीक की परीक्षण के मौके पर महापौर मंजुषा नागपुरे ने स्वयं मौके पर पहुंचकर मशीन के लाइव कार्य का बारीकी से से इसकी पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के इस तरह के क्रांतिकारी उपयोग से अब शहर के सभी प्रमुख जलस्रोतों की सफाई अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और प्रभावी तरीके से की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना पुणे महानगरपालिका की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

शहरी और ग्रामीण इलाकों में यह जलकुंभी जलभराव, भयानक दुर्गंध और मच्छरों के पनपने की समस्या का सबसे बड़ा कारण बनती है, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है.

अहेरी कृषि विभाग में १४ पद रिक्त



संवाददाता । गड़चिरोली

अहेरी तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय में कुल 14 पद रिक्त होने के कारण कृषि विभाग का कामकाज गंभीर दबाव में चल रहा है. खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं का लाभ, फसल निरीक्षण, उर्वरक-बीज की निगरानी तथा कृषि विस्तार कार्यक्रमों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. खरीफ सीजन शुरू होने के कारण इन दिनों कृषि कार्यालय में किसानों की बड़ी संख्या में आवाजाही हो रही है. ऐसे समय में मंडल कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी (गुण नियंत्रण), सहायक अधीक्षक और वरिष्ठ लिपिक जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से कई कार्यों में देरी हो रही है. नकली खद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री रोकने तथा कृषि केंद्रों की नियमित जांच के लिए पर्याप्त

अमले की आवश्यकता होती है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण निरीक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. अहेरी मुख्यालय स्थित उपविभागीय कृषि अधिकारी का पद पिछले एक वर्ष से रिक्त है, जिसका अतिरिक्त प्रभार सिरोंचा के तालुका कृषि अधिकारी के पास है. वहीं, कृषि अधिकारी (गुण नियंत्रण) का पद भी खाली होने से इसकी जिम्मेदारी भामरागड के कृषि अधिकारी को सौंपी गई है. परिणामस्वरूप एक ही अधिकारी को दो दो तहसीलों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है. अहेरी तहसील में स्वीकृत 33 पदों में से 14 पद खाली होने के कारण कृषि विभाग सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहा है. किसानों का कहना है कि यदि अतिवृष्टि, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान होता है, तो पंचनामा, सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों में भी विलंब हो सकता है. किसानों ने विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की है.

शिक्रापुर पुलिस ने दिया स्वच्छता का संदेश, 50 अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया श्रमदान

थाने से लेकर परिसर तक चला सफाई अभियान

संवाददाता । शिक्रापुर पुलिस की पहचान आमतौर पर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़ी होती है, लेकिन शिक्रापुर पुलिस ने इस बार हाथों में स्वयं श्रमदान कर परिसर को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया. पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव ने हाल ही में शिक्रापुर थाने का कार्यभार संभालने के बाद यातायात व्यवस्था सुधारने, बाजार क्षेत्र को चोरीमुक्त बनाने और विद्यालयों के आसपास ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे कई



सोशल मीडिया पर पुलिस की पहल का सराहना

जमा कचरे को ग्राम पंचायत की कचरा वाहन के माध्यम से हटाया गया. अभियान के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वयं झाड़ू, फावड़ा और सफाई उपकरणों का उपयोग किया. इस अभियान के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस की इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है. नागरिकों ने इसे जनजागरण की दिशा में सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि जब पुलिस स्वयं आगे बढ़कर स्वच्छता का संदेश दे रही है, तो समाज को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए.

जनहित के संकल्प लिए हैं. उन्होंने इन अभियानों की शुरुआत स्वयं से करने का निर्णय लिया और सबसे पहले पुलिस थाने को स्वच्छ बनाने की पहल की. सफाई

उत्साह से मनाई महाराणा

प्रताप की जयंती

संवाददाता / आमगांव

राजपूत समाज द्वारा वीर

शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती

उत्साह के साथ मनाई गई. कार्यक्रम

में समाज के महिला-पुरुष, युवा एवं

बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर

महाराणा प्रताप को आदरंजलि

अर्पित की. शाम के समय आंबेडकर

चौक से कृषि उपज बाजार समिति

तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई.

शोभायात्रा में महाराणा प्रताप की

आकर्षक झांकी सजाई गई थी,

जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित

किया. महाराणा प्रताप के शौर्य और

वीरता पर आधारित गीतों के बीच

निकली इस शोभायात्रा ने पूरे

आमगांव नगर को राष्ट्रभक्ति और

गौरव के रंग में रंग दिया.

सपनों को पूरा करने मेहनत करना जरूरी

संवाददाता । गड़चिरोली

भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गड़चिरोली जिले की सरकारी आश्रमशालाओं के 96 आदिवासी विद्यार्थियों का राष्ट्रपति भवन में आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें जीवन में बड़े सपने देखने और शिक्षा के माध्यम से उन्हें साकार करने का प्रेरणादायी संदेश दिया. राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को चॉकलेट भेंट की तथा उनसे उनके नाम, गांव, पढ़ाई और भविष्य के लक्ष्य के बारे में आत्मीयता से बातचीत की. देश के प्रथम नागरिक से हुई यह मुलाकात विद्यार्थियों के लिए अविस्मरणीय और प्रेरणादायक अनुभव साबित हुई. जिला वार्षिक आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आयोजित दिल्ली शैक्षणिक भ्रमण में गड़चिरोली,

अहेरी तथा भामरागड की सरकारी आश्रमशालाओं के 96 विद्यार्थी शामिल हुए. राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर सभी विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. राष्ट्रपति ने प्रत्येक विद्यार्थी से व्यक्तिगत रूप से संवाद करते हुए उनकी शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली. संवाद के दौरान पोटेगांव के एक छात्र ने बताया कि वह भविष्य में शिक्षक बनना चाहता है. छात्र की इस इच्छा को राष्ट्रपति ने सराहना करते हुए उसे शिक्षा में निरंतरता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. राष्ट्रपति के इस आत्मीय व्यवहार से विद्यार्थियों में नया उत्साह और आत्मविश्वास जागृत हुआ.

शिक्षणाधिकारी कार्यालय के समक्ष विमाशिसं ने दिया धरना

संवाददाता । गड़चिरोली

निजि व स्थानीय स्वराज्य संस्था अंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शाला, निजि अनुदानित विज्ञान, आदिवासी आश्रमस्कूल के शिक्षक शिक्षक कर्मचारियों की प्रलंबित समस्या हल करने के लिए विदग्ध माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से आज 26 जून को धरना आंदोलन किया गया.

राज्य के सभी शिक्षक शिक्षक केंद्र व राज्य कर्मचारियों को सिधे पुरानी पेंशन

प्रलंबित मांगों को लेकर किया ध्यानाकर्षण

योजना लागू करें, 1 नवंबर 2005 के पूर्व बिना अनुदानित, अंशता अनुदानित स्कूल तुकड़ी पर नियुक्त लेकिन शतप्रतिशत अनुदान 1 नोवंबर 2005 के बाद आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करें, वर्ष 2025-26 में अधिक का अनुदान चरण से वंचित रहे स्कूलों को अनुदान चरण तत्काल मंजूर करें, 31 मार्च को प्रलंबित बकाया देयके शिक्षणाधिकारी, शिक्षा

प्रमुखमंत्री, शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन धरना आंदोलन के बाद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया. धरना आंदोलन में जिलाध्यक्ष रविंद्र नैताम, नरेंद्र भोयार, मनोज निंबारतें, शोमदेव चाफले, अजय वर्धलवार, यादव बानबले, संजय कुनघाडकर, विनोद सालेकर, पोपेश्वर लडके, रूपेश अमलकुरीवार, किशोर पाचभाई आदि का समावेश था.

करोड़ों की लागत से बना पुल ५ वर्ष में जर्जर



संवाददाता । गड़चिरोली

आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल गड़चिरोली जिले के विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई जा रही है. इसके बावजूद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर

निर्माण गुणवत्ता व निगरानी पर उठे सवाल, जांच करने की मांग

इस पुल का निर्माण कराया गया था. पुल बनने से देवलमारी, चेरपल्ली, गढ़बामणी, सहित आसपास के 20 से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिली थी. इससे पहले यहां ब्रिटिशकालीन कम ऊंचाई वाला पुल था, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ग्रामीणों का संपर्क तहसील एवं जिला मुख्यालय से कट जाता था. ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने नए पुल के निर्माण को मंजूरी देते हुए

15 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की थी. पुल बनने के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब निर्माण के केवल पांच वर्ष के भीतर ही इसकी स्थिति चिंताजनक हो गई है. पुल के दोनों ओर की अप्रोच सड़क धंस गई है, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं सड़क पर वर्षा का पानी जमा होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है. स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण

देसाईगंज में प्रशासन तथा रेत माफिया पर उठे सवाल

संवाददाता । गड़चिरोली

देसाईगंज तहसील में प्रशासन की कथित मिलिभगत से अवैध रेत खनन का कारोबार जारी है. इसी बीच कोढाला क्षेत्र के सिंझाई रेत घाट पर पड़े की अवधि समाप्त होने के बाद भी कथित रूप से चल रहे अवैध खनन के दौरान एक मजदूर की मशीन के नीचे दबकर मौत हो गई.

मृतक का नाम जुनी वडसा निवासी विलास महादेव देवढाले (34) है. बुधवार को सुबह सिंझाई रेत घाट पर भारी मशीनों की सहायता से रेत निकाली जा रही थी और उसे ट्रैक्टरों में भरा जा रहा था. इसी दौरान चालक तथा मजदूर के रूप में कार्यरत विलास देवढाले अचानक रेत निकालने वाली मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

25 ने निभाया सामाजिक दायित्व

ग्रामीण अस्पताल में रक्तदान शिविर

संवाददाता । गड़चिरोली

सामाजिक दायित्व निभाते हुए रक्तदान जैसे जीवनरक्षक कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज बचत समूह, कोरवी तथा अदानी सीमेंट गुप्त के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण अस्पताल कोरवी में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर को नागरिकों का उत्साहपूर्ण प्रतिवाद मिला और कुल 25 लोगों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया. इसके साथ ही अनेक नागरिकों की निश्चुक्त स्वास्थ्य जांच एवं रक्त जांच भी की गई. रक्तदान को सर्वोत्तम दान माना जाता है. दुर्घटनाग्रस्त मरीजों, शल्य चिकित्सा कराने वाले रोगियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए समय-समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है. रक्त की कमी न हो तथा नागरिकों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़े, इसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कोरवी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र ठाकरे, सदरुद्दीन भामानी, मनोज अग्रवाल, डा. कृपाल सरदार, मिथुन मोडक, निनाद फुंडे, डॉ.

स्मार्ट मीटर पर जताया विरोध

आझाद समाज पार्टी व माकपा ने किया आंदोलन

संवाददाता । गड़चिरोली

महावितरण द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की कथित जबरदस्ती, फर्जी एवं अत्यधिक बिजली बिल, अनुमानित बिलिंग, उपभोक्ताओं की शिकायतों की अनदेखी तथा लापरवाह कार्यप्रणाली के विरोध में आजाद समाज पार्टी व माकपा की कम्प्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में महावितरण के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर आंदोलन किया गया.

इस प्रदर्शन में सैकड़ों नागरिक अपनी शिकायतें और भारी-भरकम बिजली बिलों की प्रतियां लेकर शामिल हुए, जिससे आंदोलन स्थल पर जनाक्रोश का माहौल देखने को मिला. आंदोलन के दौरान नागरिकों ने



महावितरण की कार्यप्रणाली से जुड़े कई गंभीर मामलों को उजागर किया. गड़चिरोली निवासी दुर्गा कुर्जेकर को घरेलू बिजली उपयोग के लिए 99,540 रुपये का बिजली बिल भेजे जाने का मामला सामने रखा गया. वहीं, वाघोली की 70 वर्षीय वृद्ध महिला शेवंता कुमरे, जो एक छोटे से कच्चे मकान में अकेली रहती हैं, उन्हें 27,000 रुपये का बिजली बिल

आंदोलनकारियों ने विभाग के समक्ष रखी ये मांगें

आंदोलनकारियों ने मांग की कि जिन उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिजली बिल प्राप्त हुए हैं, उनके घरों में महावितरण द्वारा प्रत्यक्ष जांच की जाए. मीटर, रीडिंग, बिलिंग प्रणाली, अनुमानित बिलिंग तथा गलत देयकों की जांच कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए. साथ ही स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं पर दबाव बनाना, मीटर रीडिंग लिए बिना अनुमानित बिल जारी करना तथा शिकायतों पर कार्रवाई न करना तुरंत बंद किया जाए. करीब 2 घंटे तक चले इस आंदोलन में नारेबाजी, ज्ञापन सौंपना, पीड़ित उपभोक्ताओं की समस्याओं को सामने रखना और अधिकारियों से सीधा संवाद शामिल रहा.

समस्याओं पर जवाब मांगा गया. अधिकारियों ने प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्पष्ट आश्वासन या ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं दे सके. आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राज बंसोड़ ने आरोप लगाया कि महावितरण प्रशासन द्वारा विभाग के जवाब और 'देखेंगे' जैसे गोलमोल जवाब देकर जनता की समस्याओं को टाल रहा है. आंदोलनकारियों ने अधीक्षक अभियंता के माध्यम से

सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिला अध्यक्ष राज बंसोड़, माकपा के सचिव अमोल मारकवार, जिला प्रवक्त प्रितेश अंबादे, जिला उपाध्यक्ष डा. प्रशांत सातार, युवा अध्यक्ष विक्की खोबरागडे, जिला सचिव प्रकाश बंसोड़, कोषाध्यक्ष नागसेन खोबरागडे, आरमरी युवा अध्यक्ष मंगेश बंसोड़, महिला अध्यक्ष सोनाशी लभाने सहित पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बिजली उपभोक्ता उपस्थित थे.

सचिन बरडे, राहुल सिडाम, प्रफुल राजत, वैजनाथ पोते सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग उपस्थित थे. शिविर में विनायक लिगायत, मनोज सारवा, नीलकंठ मडावी, हिमांशु सोनटक्के, शिवा कोरेटी, रविंद्र अट्टेला, पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र ठाकरे, मनोज अग्रवाल, सूरज हेमके, आशीष अग्रवाल, दिनेश बोरकुटे, रविंद्र बावणे, विशाल जांभूलकर, आकाश हिडामी, हेमराज दरों, फिरोज सोनकुकरा, एस. बी. चकाते, ए. एस. पिसे, हेमलाल देवांगन, आर. बी. सहारे, आर. बी. बावणे, नामदेव नागपुरे, विनोद गडपायले, के. एम. सूर्यवंशी तथा मिथुन मोडक ने रक्तदान कर सामाजिक सेरोकार का परिचय दिया. कार्यक्रम का संचालन सूरज हेमके, प्रस्तावनी आशीष अग्रवाल व सविता चंदनखेड़े ने आभार व्यक्त किया. शिविर को सफल बनाने में छत्रपति शिवाजी महाराज बचत समूह के अध्यक्ष नामदेव नागपुरे, सचिव सूरज हेमके, उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, निमित्त रहेजा, राजेंद्र मस्के तथा ग्रामीण अस्पताल कोरवी के चिकित्सक, अधिकारी तथा कर्मचारियों ने विशेष योगदान दिया.

जिले में दिखाई दिए मात्र ३२ सारस

वार्षिक गणना के लिए ३५ सर्वे टीम गठित की गई थीं



संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया-भंडारा जिले का वैभव माने जाने वाले प्रेम के प्रतीक सारस पक्षियों की वार्षिक गणना 20 जून को गोंदिया जिले के 53 सारस पक्षी अधिवास क्षेत्रों में हुई। गणना के पश्चात 26 जून को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जिले में 32 सारस पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई।

यह गणना प्रतिवर्ष पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में काम कर रही सेवा संस्था वन विभाग गोंदिया और नागरिकों के सहयोग से पारंपरिक एवं शास्त्रीय पद्धति से की जाती है।

इस वर्ष जिले में 35 सर्वे टीम गठित की गई थीं। हर टीम में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी के साथ 2 से 4

२०२० के बाद नहीं बढ़ी संख्या

गोंदिया जिले में सारस पक्षियों की संख्या में वर्ष २०२० के बाद जिले में अब तक बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं की गई है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। वर्ष २०२० में ४५ सारस पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष २०२१ में ३९, वर्ष २०२२ में ३४, वर्ष २०२३ में ३९, वर्ष २०२४ में २८ एवं वर्ष २०२५ में ३० पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई।

प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का समावेश किया गया था। सभी टीमों ने सुबह 4.45 से 9 बजे के दौरान सारस पक्षियों के विश्रांति स्थलों का निरीक्षण, गणना एवं आवश्यक तत्व कुछ चुने गए अधिवास क्षेत्रों में सर्वेक्षण टीम ने निरीक्षण किया। इस पूर्व तैयारी के कारण सारस पक्षियों की संख्या की जानकारी विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होने में मदद मिली। उसी प्रकार एक ही पक्षी का एक से

अंतिम आंकड़े सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद घोषित किए जाने की जानकारी सेवा संस्था के अध्यक्ष सावन बहेकार ने दी है। गणना से पूर्व एवं उसके बाद दो से तीन दिन तक कुछ चुने गए अधिवास क्षेत्रों में सर्वेक्षण टीम ने निरीक्षण किया। इस पूर्व तैयारी के कारण सारस पक्षियों की संख्या की जानकारी विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होने में मदद मिली। उसी प्रकार एक ही पक्षी का एक से

अधिक स्थानों पर पंजीयन की संभावना को टालने के लिए सभी टीमों ने समन्वय स्थापित कर विशेष दक्षता रखी।

यह गणना केवल सारस पक्षी की संख्या की जांच करने तक सिमित न होकर उनके अधिवास की वर्तमान स्थिति, प्रजनन क्षेत्र एवं संभावित खतरों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार है। सारस पक्षी गणना गोंदिया के उपवन संरक्षक पवनकुमार जोग, सेवा संस्था के अध्यक्ष सावन बहेकार के मार्गदर्शन में हुई। इस गणना में गोंदिया के जिलाधिकारी मंगेश गोदावले भी उपस्थित रहे। इसके अलावा सहायक वन संरक्षक एवं गोंदिया तथा आमगांव के वन परिक्षेत्र अधिकारियों के साथ ही सेवा संस्था के शाशांक लाडेकर, कन्हैया उदापुरे, अभिजीत परिहार, डिलेश कुसुराम, सुशील बहेकार, भास्कर कापसे, बी.एन.एच.एम. के मुकुंद धुर्वे का योगदान रहा है।

गोंदिया की स्वास्थ्य सेविका बनी 'मसीहा', चलती ट्रेन में कराई सुरक्षित प्रसूति

संवाददाता / गोंदिया

अगर आप आपने कर्तव्य और समय की गंभीरता को समझते हैं तो चलती ट्रेन में भी चमत्कार हो सकता है। इसी तरह का एक चमत्कार नागपुर से मुंबई की ओर जा रही दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बुधवार 24 जून को हुआ। इस ट्रेन में एक गर्भवती महिला को अचानक लेबर पेन होने लगा।



जिले के काटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत मरारटोला उपकेंद्र में कार्यरत एनएम आशा सेविका राजश्री भोंडे (नेवारे) को जब इसकी जानकारी मिली तो वह बिना

चिकित्सा सामग्री नहीं होते हुए भी राजश्री भोंडे ने समय की गंभीरता को पहचाना

सुरक्षित रूप से प्रसूति कराई। उनकी इस हिम्मत और संतर्कता से माँ और नवजात शिशु की जान बच सकी। जिससे संपूर्ण जिले में हर स्तर पर आशा सेविका भोंडे की सराहना हो रही है।

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस जलांगल स्टेशन से थोड़ा आगे निकली ही थी कि अचानक ट्रेन में बैठी गर्भवती महिला को तीव्र लेबर पेन शुरू हुआ। अगला स्टेशन आने में काफी समय होने से महिला के परिजन एवं ट्रेन में बैठे अन्य यात्री पूरी तरह से घबरा गए। इसी ट्रेन से यात्रा कर रही गोंदिया

डरे स्थिति को संभालने का प्रयास करने लगी। चलती ट्रेन में आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध न होते हुए भी राजश्री भोंडे ने समय की गंभीरता को पहचाना और अपने अनुभव के बदीलत चलती ट्रेन में महिला की सुरक्षित रूप से सफल प्रसूति करवाकर नवजात शिशु और माँ की जान बचाई। इसके बाद रेलवे प्रशासन से संपर्क कर चालीसगांव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर वहां पहले से तैनात एम्बुलेंस की मदद से शिशु और माँ को आगे के उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल रेफर किया गया।

अतिक्रमण की कार्रवाई का डर, दुकानदारों ने एक लाइन से सजा लीं अपनी दुकानें

दुकानें सड़क तक लगाने से हर ५ मिनट में यातायात प्रभावित होता था

संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया शहर में ऐसी कोई गल्लि नहीं जहां पर अतिक्रमण न हो, लेकिन सबसे अधिक दिक्कतों का सामना शहर का मुख्य मार्ग इंदिरा गांधी स्टेडियम से लेकर गोंदिया बाजार विभाग के मार्गों पर देखा जाता था।

अतिक्रमण की कार्रवाई से बचने के लिए एक लाइन में दुकानें सजा दी हैं। कई वर्षों के बाद लाइन में दुकानें होने से यातायात की समस्या हल हो गई है। इस तरह का नजारा बुधवार 24 जून को देखा गया है।

इन मार्गों पर दुकानें सड़क तक आ गई थीं। जिस वजह से



यातायात हर 5 मिनट में प्रभावित हो जाता था, जिसे देखते हुए गोंदिया नगर परिषद में सूचना दी थी कि निर्धारित समय में अतिक्रमण हटाएं तथा दुकानें अपने ही स्थान पर लगाएं, अन्यथा अतिक्रमण हटाया जाएगा।

लेकिन विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता 22 जून तक होने से अतिक्रमण की कार्रवाई को स्थगित किया गया था। लेकिन दुकानदारों में इतना डर निर्माण हो गया है कि बता दें कि शहर का अतिक्रमण हटाने के लिए गोंदिया

नगर परिषद द्वारा शहर में सूचना देकर 3 जून के पूर्व अतिक्रमण हटाए लेकिन विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता घोषित होने से अतिक्रमण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। 22 जून को आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से फिर से चर्चा शुरू हो गई थी कि अब अतिक्रमण की कार्रवाई की मुहिम प्रभावी रूप से चलाई जाएगी। जिसे देखते हुए शहर के दुकानदारों ने जो दुकानें सड़क तक सजती थीं अब सड़क छोड़कर एक लाइन में दुकानें लगाईं। अब मुख्य मार्गों का यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

सामाजिक न्याय दिवस कार्यक्रम

संवाददाता / गोंदिया

सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की 152वीं जयंती के अवसर पर 26 जून को सुबह 10 बजे सामाजिक न्याय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

यह कार्यक्रम पतंगा मैदान स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन में होगा। कार्यक्रम में शासकीय आवासीय

विद्यालयों के कक्षा 10वीं के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा गटई स्टॉल योजना के लाभार्थियों को स्टॉल वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम का लाभ लेने का आह्वान किया गया है।

खातिया में उत्साह से मनाया गया एकल महिला दिवस

संवाददाता / गोंदिया

तहसील अंतर्गत ग्राम खातिया में ग्राम पंचायत के माध्यम से महिला बचत समूह भवन में एकल महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एकल महिलाओं की समस्याओं को जानना तथा उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मार्गदर्शन करना था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हिरनबाई मेश्राम ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में सरपंच ललित तावाडे, ग्राम पंचायत सदस्य विजेंद्र मेश्राम, सूरजलाल खोटेले, रक्षा फुंडे, ललिता कोल्हटकर, ग्राम पंचायत अधिकारी दिव्यानी डोंगरे, आईसीआरपी योगिता गिरीपुंजे,



मयूरी खोटेले, ग्रामसंघ अध्यक्ष माधुरी रहिले समेत बड़ी संख्या में एकल महिलाएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर हिरन मेश्राम, कांताबाई बागडे, कामन मेश्राम, भागरता चंदेले, भीमाबाई मेश्राम, अनुबाई नांन्हे, इतला कोल्हटकर, सुंदरबाई तावाडे, जामवंता चौरे, उर्मिला थेर और बिंदू बंसोड समेत कई महिलाओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव

पंचायत प्रशासन से संपर्क कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा संजय गांधी निराधार योजना, श्रवणबाल योजना, गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन भरवाकर पात्र नागरिकों को लाभ दिलाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन योगिता गिरीपुंजे तथा आभार प्रदर्शन दिव्यानी डोंगरे ने किया। आयोजन को सफल बनाने में ग्राम पंचायत कर्मचारी आनंद बागडे, जयपाल गिरीपुंजे और जितेंद्र रहिले समेत अन्य कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

जिले में औषधियुक्त सब्जियों की मांग बढ़ी

संवाददाता / गोंदिया

ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र के नागरिक बारिश के मौसम में जंगली सब्जियों का स्वाद लेते हैं। लेकिन इस वर्ष बारिश को विलंब होने से जंगल में सब्जियां नहीं उग पाई हैं। जिससे जंगली सब्जियां बाजार में उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। फिलहाल जंगली सब्जियों के शौकीन इन औषधि गुणों से भरपूर सब्जियों के इंतजार में हैं।

मानसून जैसे ही शुरू होता है ग्रामीण परिसर में खारखुटी, शेरडीरे, आंबाली सब्जी, शेरफरे, बांस के वास्ते, लेंगला सब्जी, कानफुटी, भुईआवला, करटोली व अन्य जंगली सब्जियां उग जाती हैं। यह जंगली सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए पोषक और औषधियों के गुण होने से इन सब्जियों को विशेष महत्व है।



मानसून की शुरुआत में जंगल या पहाड़ी पर जंगली सब्जियां मिलती हैं।

ग्रामीण परिसर के नागरिक और आदिवासी युवा सुबह जंगल में जाकर जंगली सब्जियां इकट्ठी करते हैं। जिससे ग्रामीण या आदिवासियों को रोजगार मिलता है। इन सब्जियों को बाजार में बेचकर वे मिलने वाले पैसों से परिवार का जीवनयापन करते हैं। इन सब्जियों की बाजार में बढ़ी मांग है। बारिश के अभाव में आदिवासियों का रोजगार छीन गया है। जंगली सब्जियां पहाड़ व जंगल में उगने से दिन-ब-दिन सब्जियां दुर्लभ होती जा रही हैं।

अभियान को प्रभावी ढंग से चलाएं: दोन्तुला

गोंदिया: वर्षा ऋतु के दौरान दूषित पानी, अस्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के कारण डायरिया (अतिसार) जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान 2026 चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 जुलाई तक पूरे जिले में संचालित किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा

दोन्तुला ने सभी संबंधित विभागों तथा नागरिकों से अभियान को प्रभावी ढंग से सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि डायरिया विशेष रूप से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सुरक्षित पेयजल, साबुन से हाथ धोने की आदत, स्वच्छ वातावरण तथा स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करके इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

विधायक बडोले के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे

संवाददाता / गोंदिया एक आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित गुट) के विधायक राजकुमार बडोले की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पोशाख तथा भाजपा के कमल चिन्ह को अपमानजनक तरीके से प्रदर्शित किया गया था। यह मामला सोशल मीडिया पर तथा खबरों के माध्यम से सामने आया। जिसे देखते हुए भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

के कार्यकर्ताओं ने विधायक राजकुमार बडोले का निषेध व्यक्त करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाकर संबंधित पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाए इस तरह की मांग का ज्ञापन गोरगांव तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री व गृहमंत्री के नाम सौंपा गया है। यह ज्ञापन गुरुवार 25 जून को गोरगांव तहसील कार्यलय में दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक

संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के राकापा अजित गुट के विधायक राजकुमार बडोले की प्रमुख उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के कमल चिन्ह तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पोशाख का अपमानजनक प्रदर्शन किया गया। उपरोक्त मामला निदनीय है।

यह मामला किसी एक संगठन या राजनीतिक दल के विरोध तक सिमित नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ी है। इस तरह का ज्ञापन गोरगांव तहसील पूर्व भाजपा अध्यक्ष साहेबलाल कटरे के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान विजय राणे, दुर्गाप्रसाद ठाकरे, मोरेश्वर कटरे, जे.डी. जगनीत, उमैदर मेंटे, श्रीकांत चौधरी, रेवेंद्रकुमार बिसेन, सुनील कोहडे, डा. योगेश

हरिणखेडे, सुरेंद्र पटले, हीरा रहांगडाले, बाबुलाल गौतम, मेघनाथ पारधी, नितीन कटरे, किशोर पारधी, शंकर पटले,

सुभाष पटले, नारायण पटले, श्रीकांत कांबले सहित बड़ी संख्या में भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

२१ हजार किसानों का होगा कर्ज माफ, सूची हो रही तैयार

किसानों के नाम बैंक खाता क्रमांक के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे नियमित कर्ज वापसी वालों को ५० हजार तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा



संवाददाता / गोंदिया

प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोत्तरी के चलते किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। समय पर कर्ज नहीं अदा कर पाने के कारण उन्हें नया फसल कर्ज ही नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी ओर कर्ज की राशि भी लगातार बढ़ती जाती है। जिसे देखते

हुए राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना 2026 की घोषणा की है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए लागू किए गए नियम एवं शर्तों के तहत जांच-पड़ताल कर जिला उपनिबंधक कार्यालय की ओर से पात्र लाभार्थी किसानों की सूची बनाने का

काम इन दिनों युद्धस्तर पर चल रहा है। गोंदिया जिले में लगभग 21 हजार 77 किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होने की बात प्राथमिक जांच-पड़ताल में सामने आयी है। जिनकी सूची को अंतिम रूप देने का काम अब किया जा रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की कर्जमुक्ति के लिए राज्य सरकार ने यह योजना

तहसीलवार पात्र लाभार्थी

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना २०२६ के तहत गोंदिया जिले में पात्र लाभार्थियों की संख्या कुल २१ हजार ७७ बताई गई है। जिनके नाम उनके खाते के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। २४ जून तक जिले में कुल २१ हजार ७७ किसान इसके लिए पात्र पाए गए हैं। तहसीलवार देखा जाए तो गोंदिया तहसील में ३२३२, तिरोंडा में २४९०, गोरगांव में ३९७६, आमगांव में ९७७९, सालेकसा में ८२५, देवरी में २८३७, सड़क अर्जुनी में २५३९ एवं अर्जुनी मोरगांव तहसील में ३४७९ किसान इस योजना के लाभ के लिए पात्र पाए गए हैं।

घोषित की है। योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक का जिन किसानों का कर्ज बकाया है। उन किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्जमाफी दी जाएगी। उसी प्रकार प्रतिवर्ष नियमित रूप से कर्ज की वापसी करने वाले किसानों को भी 50 हजार रुपए तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए पात्र

लाभार्थी किसानों की सूची तैयार करने की सूचना शासन की ओर से दी गई थी। जिसके बाद जिले के जिला उपनिबंधक कार्यालय, जिला सहकारी बैंक एवं जिला प्रशासन इस काम में लगे हुए हैं। पात्र किसानों के नाम उनके बैंक खाते क्रमांक के साथ शासकीय पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटिंग प्रेस, गुरुनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरुनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित।

संपादक :- चंद्रकांत खंडेलवाल, पी.आर.पी.एक्ट के तहत जिम्मेदार *

शिवका

आदेशान्वये,
(एच. एस. डोंगरवार)
सहायक अधीक्षक,
दिव्याणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, गोंदिया